Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

भाग-1

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: BRPM11

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

भारतीय अर्थव्यवस्था

(बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

भाग–1

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

BPSC DLP

विषय सूची (Contents)

1.	**भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय**	**5-20**
1.1	अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था	5
1.2	भारतीय अर्थव्यवस्था : प्रकृति एवं वर्तमान प्रवृत्तियाँ	8
1.3	अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	10
1.4	आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि	10
1.5	आर्थिक विकास के मापन	14
1.6	आर्थिक विकास की रणनीति	17
2.	**राष्ट्रीय आय**	**21-37**
2.1	राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा	21
2.2	राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ	28
2.3	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय	34
3.	**भारत में आर्थिक नियोजन**	**38-52**
3.1	नियोजन : अभिप्राय, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषताएँ एवं प्रकार	38
3.2	योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग	40
4.	**समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन**	**53-79**
4.1	समावेशी विकास	53
4.2	समावेशी संवृद्धि	54
4.3	वित्तीय समावेशन	54
4.4	सामाजिक समावेशन	58
4.5	गरीबी	59
4.6	बेरोज़गारी	69
5.	**कृषि**	**80-126**
5.1	आर्थिक विकास में कृषि का योगदान	80
5.2	भारतीय कृषि की विशेषताएँ	81
5.3	भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार	86
5.4	हरित क्रांति	89
5.5	सिंचाई	93

5.6 कृषि साख 94
5.7 कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकियाँ 100
5.8 खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक 103
5.9 सार्वजनिक वितरण प्रणाली : उद्देश्य एवं सीमाएँ 108
5.10 सब्सिडी : खाद्य सब्सिडी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी 109
5.11 कृषि से संबंधित अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रक 111
5.12 कृषि से संबंधित योजनाएँ 114

6. उद्योग एवं सेवा क्षेत्र **127-184**
6.1 औद्योगीकरण : आशय एवं उत्पादन के क्षेत्र 127
6.2 भारतीय औद्योगिक नीति 128
6.3 उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण 133
6.4 निवेश एवं विनिवेश 142
6.5 सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग 144
6.6 भारत में सार्वजनिक उद्यम: महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न 145
6.7 भारत में उद्योग 147
6.8 औद्योगिक अस्वस्थता/रुग्णता 154
6.9 औद्योगिक वित्त 155
6.10 औद्योगीकरण से संबंधित प्रमुख योजनाएँ 159
6.11 सेवा क्षेत्र में भारतीय परिदृश्य 165
6.12 सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएँ 172
6.13 आधारभूत अधोसंरचना 177

7. बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली **185-228**
7.1 मुद्रा और बैंकिंग 185
7.2 परिसंपत्तियाँ एवं देयता सृजन 202
7.3 भारतीय रिज़र्व बैंक 203
7.4 शेयर बाज़ार, प्रतिभूति बाज़ार एवं सेबी 208
7.5 भारत में म्यूचुअल फंड एवं बीमा क्षेत्र 213
7.6 डिपॉजिटरी प्रणाली, कमोडिटी एक्सचेंज एवं डेरिवेटिव्स 214
7.7 मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति 215

अध्याय
1

भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय (Indian Economy : General Introduction)

प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। मध्यकाल में भारत का व्यापार अरब देशों, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों तथा यूरोपीय देशों तक फैला हुआ था, लेकिन 18वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, फलतः वह दयनीय स्थिति में आ गई। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में गति प्रदान करने तथा विकास की निरंतरता को बनाए रखने हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1991 में नई आर्थिक प्रणाली लागू कर उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा दिया गया, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर बढ़ाई जा सके।

1.1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था *(Economics and Economy)*

अर्थशास्त्र *(Economics)*

अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। **एडम स्मिथ** को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र की अवधारणा में बैंकिंग, राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि को भी शामिल किया जाता है।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (Branches of economics)

अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro economics)

- व्यष्टि-अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक व्यक्तिगत फर्म या उत्पादन गृह अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता।
- इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा उस उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है।

2. समष्टि अर्थशास्त्र (Macro economics)

- समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
- इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित किया जाता है।
- रोज़गार, मुद्रा, सामान्य कीमत, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

अर्थव्यवस्था *(Economy)*

किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए मुद्रा (Money) को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही **अर्थव्यवस्था** कहलाती है। 'अर्थव्यवस्था' शब्द को किसी देश के साथ जोड़कर प्रायः पूर्ण बनाया जाता है, जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था आदि। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली अवधारणा है जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं उनके स्तर से होता है। वह क्षेत्र एक गाँव, राज्य या संपूर्ण देश भी हो सकता है।

आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय को शामिल किया जाता है–

उत्पादन (Production) : उत्पादन का अर्थ आगतों या कारकों को उत्पाद में बदलना है।

उपभोग (Consumption) : अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही उपभोग कहलाता है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 50 प्रतिशत हो तथा इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की आजीविका के लिये निर्भरता हो तो उस अर्थव्यवस्था को 'औद्योगिक अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है।
- व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेड मार्क कहा जाता है।
- निर्माण एवं विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- भारत को एक श्रम-आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वानिकी, मत्स्यन तथा खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमशीलता उत्पादन के कारक हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' थी।
- बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा तथा पर्यटन आदि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं।
- भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ श्रम आधिक्य की स्थिति रहती है।
- आय वितरण में असमानता, जीवन निर्वाह का निम्न स्तर, व्यापक बेरोज़गारी, असंतुलित आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरण का निम्न स्तर इत्यादि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
- सामाजिक प्रगति सूचकांक तीन व्यापक आयामों मानव की बुनियादी आवश्यकताएँ, सुख के आधार और अवसर पर आधारित है।
- जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश (योगदान/भाग) बढ़ता जाता है।
- मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी की जाती है।
- अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार 'अमर्त्य सेन' को मिला था जबकि वर्ष 2017 का रिचर्ड एच थेलर को मिला है।
- पूंजी निर्माण के तीन आवश्यक घटकों में बचत, बचत के गतिशीलन हेतु वित्तीय संस्थाएँ तथा विनियोग को शामिल किया जाता है।
- भारत में पूंजी निर्माण आँकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिज़र्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण विकास हुआ।
- किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है।
- लैगाटम समृद्धि सूचकांक यह दर्शाता है कि किस प्रकार समृद्धि प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार समृद्धि विश्व में बदलाव ला रही है।
- श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं।
- भारत को निकट भविष्य में 8% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास करना चाहिये।
- मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई) का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री 'महबूब-उल-हक' के द्वारा किया गया।
- कारोबार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है?
53–55वीं, B.P.S.C. (Pre)
(a) समाजवादी (b) गांधीवादी
(c) मिश्रित (d) स्वतंत्र

2. यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए-
48-52वीं, B.P.S.C. (Pre)
(a) एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में।
(b) एक श्रम-आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में।
(c) एक व्यापार-आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में।
(d) एक पूंजी-आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में।

3. जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) का अंश-
47वीं, B.P.S.C. (Pre)
(a) पहले घटता है, तत्पश्चात् बढ़ता है।
(b) पहले बढ़ता है, तत्पश्चात् घटता है।
(c) बढ़ता जाता है।
(d) स्थिर रहता है।

4. पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण विकास हुआ है? **45वीं, B.P.S.C. (Pre)**
(a) प्राथमिक क्षेत्र (b) द्वितीयक क्षेत्र
(c) तृतीयक क्षेत्र (d) खनन क्षेत्र

5. अर्थशास्त्र में 1998 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला?
45वीं, B.P.S.C. (Pre)
(a) सोलो (b) मार्शल
(c) अमर्त्य सेन (d) पॉल सेम्यूएलसन

6. भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है-
39वीं, B.P.S.C. (Pre)
(a) समाजवादी व्यवस्था पर
(b) मिश्रित अर्थव्यवस्था पर
(c) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर
(d) गांधीवादी अर्थव्यवस्था पर

7. अर्थशास्त्र में 2017 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला?
(a) रिचर्ड हेंडरसन (b) काजुओ इशीगुरो
(c) रिचर्ड एच थेलर (d) राइनर वाइस

8. मानव विकास रिपोर्ट, 2016 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रम है–
(a) 133 वाँ (b) 134 वाँ
(c) 131वाँ (d) 139 वाँ

9. निम्नलिखित में से कौन-सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है?
(a) वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
(b) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि।
(c) किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
(d) जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि।

10. मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है-
(a) पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
(b) निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षिक उपलब्धि
(c) जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
(d) मुद्रा स्फीति, बेरोज़गारी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद

11. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है?
(a) प्राथमिक क्षेत्र
(b) द्वितीयक क्षेत्र
(c) तृतीयक क्षेत्र
(d) सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं।

12. भारत में पूंजी निर्माण आँकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है?
(a) भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
(b) भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक
(c) भारतीय रिज़र्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक
(d) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण

13. 'कारोबार सुगमता सूचकांक' निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
(a) विश्व बैंक (b) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(d) विश्व व्यापार संगठन (c) इनमें से कोई नहीं

14. अर्थव्यवस्था में जब प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का एक साथ विकास होता है तो यह विकास कहलाता है–
(a) संतुलित विकास (b) असंतुलित विकास
(c) स्थायी विकास (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

15. भारतीय अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जा सकता है?
    (a) एक विकसित अर्थव्यवस्था
    (b) एक विकासशील अर्थव्यवस्था
    (c) एक गतिहीन अर्थव्यवस्था
    (d) एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था

16. 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' वह अर्थव्यवस्था है जिसमें-
    (a) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व हो।
    (b) आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग हो।
    (c) वृद्ध एवं कुटीर उद्योगों का सह-अस्तित्व हो।
    (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तरमाला

1. (c)	2. (b)	3. (c)	4. (c)	5. (c)	6. (b)	7. (c)	8. (c)	9. (b)	10. (c)
11. (c)	12. (a)	13. (a)	14. (a)	15. (b)	16. (a)				

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। क्या कारण था कि भारत ने पूँजीवादी एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के बदौलत मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? सविस्तार वर्णन करें।
2. वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत को उभरती अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा गया है, क्या आप सहमत हैं? इस संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति एवं वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख करें।
3. भारत की अर्थव्यवस्था के विशेष संदर्भ में आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का तुलनात्मक वर्णन करें। इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करते हुए उचित समाधान प्रस्तुत करें।
4. किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास की रणनीति क्या होती है? आर्थिक विकास के मापन की विधियों पर चर्चा करते हुए यह बताएँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने हेतु मानव विकास क्यों आवश्यक है?

अध्याय
2

राष्ट्रीय आय (National Income)

राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है, जो नीति-निर्माण एवं कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप होती है। राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने व प्राथमिकताओं को स्थापित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण सूचकांक है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिये वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे।

2.1 राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा *(Meaning and Concept of National Income)*

राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पादित अंतिम 'वस्तुओं एवं सेवाओं' के मौद्रिक मूल्य से होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक लेखा वर्ष की अवधि के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाज़ार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा एवं विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा *(Concept of national income)*

- राष्ट्रीय आय में किसी एक समय पर उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक को नहीं, बल्कि किसी समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है।4
- राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की **बाज़ार कीमत** पर गणना की जाती है और एक वस्तु की कीमत एक बार ही शामिल की जाती है, इसलिये अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है, ताकि दोहराव से बचा जा सके।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं-

सकल घरेलू उत्पाद *(Gross domestic product–GDP)*

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिकों एवं गैर-नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष (भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च) में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को **सकल घरेलू उत्पाद** कहते हैं।

विदेशियों द्वारा पूंजी एवं तकनीकी का जो निवेश भारत के घरेलू क्षेत्र में किया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्य को भी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है-

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) = उपभोग (C) + निवेश (I) + सरकारी व्यय (G) + [कुल आयात (X) – कुल निर्यात (M)]

सकल राष्ट्रीय उत्पाद *(Gross national product–GNP)*

किसी देश के नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर अथवा बाहर एक निश्चित समयावधि, सामान्यत: एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को **सकल राष्ट्रीय उत्पाद** कहते हैं।

अध्याय
3

भारत में आर्थिक नियोजन (Economic Planning in India)

आर्थिक नियोजन (आयोजन) योजनाबद्ध तरीके से किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। आर्थिक नियोजन में सामाजिक नियोजन की अवधारणा स्वत: ही सम्मिलित रहती है। भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में नियोजन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। आर्थिक नियोजन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं उन्नति के लिये स्वीकार किया गया है।

भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्रतर बनाना नीतिगत कार्यों का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ विकास के लिये अनुकूल परिवेश तैयार करना तथा लक्षित कार्यों को नियोजित तरीके से पूर्ण करने के लिये नियोजन अनिवार्य है।

3.1 नियोजन : अभिप्राय, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषताएँ एवं प्रकार *(Planning : Significance, Objective, Requirement, Features and Type)*

नियोजन का अभिप्राय *(Significance of planning)*

राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, साथ ही सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रण तथा समन्वय किया जा सके ऐसी अवधारणा **नियोजन** कहलाती है।

नियोजन के उद्देश्य *(Objectives of planning)*

- संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना।
- निर्धनता को समाप्त करना।
- बेरोज़गारी दूर करना।
- आधारभूत संरचना का विकास करना।
- कृषि एवं उद्योग का विकास सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय के साथ ही साथ विकास की गति को तीव्र करना।

नियोजन की आवश्यकता *(Requirement of planning)*

- गरीबी, बेरोज़गारी कम करने के लिये।
- निम्न उपभोग स्तर को बढ़ाने के लिये।
- गरिमाहीन जीवन शैली के उन्नयन हेतु।
- उद्योग एवं व्यापार के अभाव को कम करने के लिये।
- कौशल एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव को कम करने के लिये।

नियोजन की विशेषताएँ *(Features of planning)*

- भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वभाव निदेशात्मक है।
- आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने में प्रोत्साहन को वरीयता दी जाती है।

अध्याय
4

समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन (Inclusive Development and Social Inclusion)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरणार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ **समावेशी विकास** अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं **सामाजिक समावेशन** समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवंचन से मुक्ति समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है।

4.1 समावेशी विकास *(Inclusive Develoment)*

समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी विकास है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये **बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)** की अवधारणा का केंद्र बिंदु **तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास** रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन-सहन का वातावरण तथा अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता आदि है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोज़गार की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी विकास में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी विकास स्थापित करने के महत्त्वपूर्ण घटक *(Important components to establish inclusive development)*

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी सामान्य एवं कमज़ोर वर्ग के बेरोज़गारों के लिये विशेष उपबंध करना। रोज़गार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना, ताकि इस क्षेत्र में निवेश तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास पर अधिक सार्वजनिक व्यय हो।

अध्याय
5

कृषि
(Agriculture)

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। स्वतंत्रता से पूर्व आय के साधन के रूप में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2017–18 की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान लगभग 16% है। वर्ष 1950–51 में यह हिस्सा लगभग 51% था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो कृषि की भागीदारी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की तुलना में कम है। खाद्यान्न उत्पादन जहाँ 1951–52 में मात्र 52 मिलियन टन था वहीं 2016–17 में यह बढ़कर 275.7 मिलियन टन हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर लगभग 4.72% थी वहीं नौवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर क्रमशः 2.5%, 2.4%, 3.2% रही। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया।

5.1 आर्थिक विकास में कृषि का योगदान
(Contribution of Agriculture in Economic Development)

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्त्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950–51 में यह लगभग 51 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में यह लगभग 14.2 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई शृंखला (आधार वर्ष 2011–12) के आधार पर 2016–17 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का सकल मूल्य संवर्द्धन (GVA) में योगदान 17.4 प्रतिशत था, जबकि वर्ष 2017–18 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा कुल जी.वी.ए. (वर्तमान कीमतों पर) में 16.4 प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सकल मूल्य संवर्द्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्त्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

रोज़गार

भारत में कृषि रोज़गार का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में आज भी लगभग 50 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 251.57 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में बढ़कर 275.7 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) हो गया है। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्त्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्त्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्त्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों, जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों, चीनी उद्योग को गन्ने आदि की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्त्वपूर्ण योगदान

कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यात का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।

अध्याय
6

उद्योग एवं सेवा क्षेत्र
(Industry and Service Sector)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये औद्योगीकरण एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। औद्योगीकरण से अर्थव्यवस्था के ढाँचे में व्यापक एवं दीर्घकालीन परिवर्तन आता है। औद्योगीकरण किसी राष्ट्र की प्रगति एवं संपन्नता का आधार ही नहीं, वरन् उसके विकास का मापदंड भी माना जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिये विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण को अधिक महत्ता दी जाती है।

प्राचीनकाल में भारत शिल्प, वस्त्र, रत्न-आभूषण एवं मसालों आदि के लिये प्रसिद्ध था, परंतु ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय उद्योग पूर्णत: गर्त में चला गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में उद्योगों के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए तीव्र औद्योगीकरण हेतु योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किये गए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई।

नब्बे के दशक में आर्थिक मंदी का सामना करने के लिये भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों हेतु नई आर्थिक नीति को अपनाया। नई आर्थिक नीति के द्वारा भारत में औद्योगीकरण को नई दिशा एवं दशा मिली है।

6.1 औद्योगीकरण : आशय एवं उत्पादन के क्षेत्र
(Industrialization : Meaning and Sector of Production)

औद्योगीकरण का आशय राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढाँचे में उद्योगों की बहुलता से है जिससे सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रमशक्ति के प्रयोग हेतु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धीरे-धीरे सामान्यतया राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता जाता है तथा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है।

दूसरे शब्दों में, प्राथमिक उत्पादों को द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को औद्योगीकरण कहते हैं। यह कार्य विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके लिये उद्योगों में निवेश अत्यंत आवश्यक है। औद्योगीकरण द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में, उद्योगों के उत्पादन में बहुलता एवं सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाया जाता है।

उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उत्पादन क्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है-

- **प्राथमिक क्षेत्र (Primary sector) :** नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें प्राथमिक वस्तुएँ कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
- **द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector) :** प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्द्धन द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन्हें द्वितीयक वस्तुएँ कहा जाता है तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं।
- **तृतीयक क्षेत्र (Tertiary sector) :** अदृश्य सेवाओं को तृतीयक वस्तुएँ कहते हैं तथा ऐसी सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (C.S.O.) द्वारा उत्पादन क्षेत्रों का किया गया वर्गीकरण निम्नलिखित है-

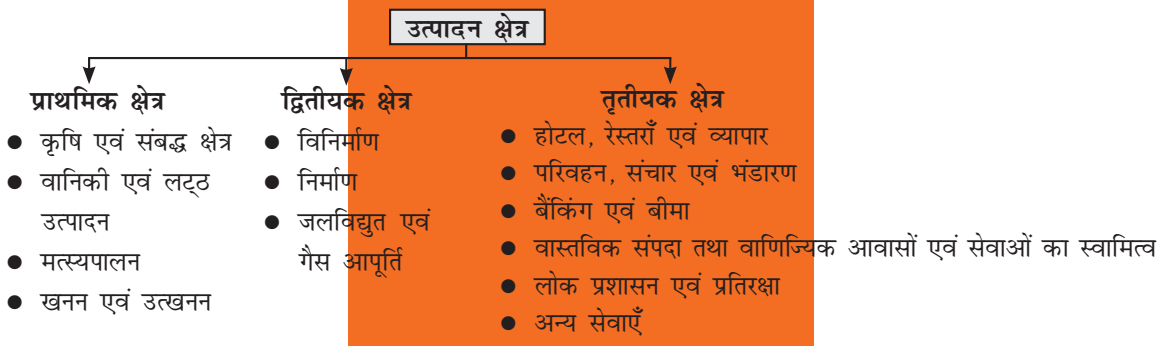

अध्याय
7

बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली
(Banking and Financial System)

बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकतानुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक नियोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिये बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। दूसरी ओर, वित्तीय प्रणाली से आशय बाज़ार की संस्थाओं से है जो कि अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

7.1 मुद्रा और बैंकिंग *(Money and Banking)*

मुद्रा *(Money)*

मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, "मुद्रा ऐसी कोई भी संपत्ति है जिसमें क्रयशक्ति के अस्थायी निवास के रूप में कार्य करने की क्षमता हो।" दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि "मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है।" मुद्रा की उत्पत्ति विनिमय के माध्यम के रूप में हुई है। अतः कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों (जिसमें ऋण भी सम्मिलित है) को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है, उसे मुद्रा कहते हैं।

मुद्रा के प्रकार (Type of money)

मुद्रा के दो प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं:

- **वैधानिक मुद्रा (Legal currency) :** वह मुद्रा जिसका निर्गमन सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया है। वैधानिक मुद्रा में रिज़र्व बैंक धारक को उतनी रकम अदा करने का वचन देता है, जितने मूल्य की करेंसी है।
- **साख मुद्रा (Credit money) :** वह मुद्रा जिसका भुगतान चेक या अन्य माध्यमों से किया जाता है। यह एक ऐच्छिक मुद्रा है, जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं है। सामान्यतः साख मुद्रा के 5 रूप प्रचलित हैं– प्रतिज्ञा-पत्र (Bond), चेक (Cheque), हुंडी (Hundi), विनिमय-पत्र (Exchange Deed), बैंक-ड्राफ्ट (Bank Draft)

सांकेतिक मुद्रा (Token money)

यह वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु से बनी होती है। उदाहरण- भारतीय सिक्के।

प्रामाणिक मुद्रा (Standard money)

यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे 'प्रामाणिक मुद्रा' कहते हैं। सोने और चांदी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा ही होते हैं।

प्लास्टिक मनी (Plastic money)

विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किये गए डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड आदि को 'प्लास्टिक मनी' कहा जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा बैंक खाते में जितनी धनराशि जमा हो उतने तक ही खरीदारी या निकासी की सुविधा होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में धनराशि न होने पर भी कुछ निकासी या खरीदारी की जा सकती है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456